NO. 24

जन आन्दोलनोंका नेतृत्व करने वाली कम्युनिस्ट पार्टीके खिलाफ़ कांग्रेस सरकारोंके ज़िहाद का असली मतलब है

53

मेहनतकश जनता पर खुला हमला !

लाठी, गोली और जेल से जनता का दमन और ज़मींदारों-पूँजीपतियोंकी हिफ़ाज़त करनेकी नीतिका मुहँतोड़ जवाब दो !

बी. टी. रणदिवे

मूल्य २ आना

27-4-51

जनवादी आन्दोलनके नेतृत्व पर हमला

केन्द्रीय सरकारकी पूरी रज़ामन्दी और हिदायतोंके अनुसार प्रान्तीय कांग्रेस मंत्रिमण्डलोंने हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ चौतर्फ़ा हमला बोल दिया है।

बंगाल सरकारने पार्टीको गैरक़ानूनी क़रार दिया है। उसने पार्टीकी स्थापना करने वालोंमें एक **कॉ. मुज़फ़्फ़र अहमद,** बंगाल असेम्बलीके सदस्य और सरकारी नीतिके जबर्दस्त आलोचक **कॉ. ज्योति बसु** तथा **कॉ. अरुण बोस, कॉ. विश्वनाथ मुकर्जी** आदि पार्टीके अनेक सदस्यों और किसान आन्दोलनोंके नेताओंको जेलमें डाल दिया है। बंगाल सरकारने पार्टीके दफ़्तर पर सील लगा दी है और दैनिक अख़बार "**स्वाधीनता**" का प्रकाशन बन्द कर दिया है क्योंकि उसे मज़दूर वर्ग और आम जनताकी आवाजसे भय लगता है।

बंगाल सरकारकी इस कार्रवाईके बाद ही पं० नेहरूने केन्द्रीय धारासभामें भाषण दिया; जिसमें उन्होंने खुद अपनी ही सरकारकी दिवालिया नीति और पूँजीपतियोंकी सर्वग्रासी भूखके कारण पैदा हुए जनताके असन्तोष और बढ़ती हुई हड़तालोंकी लहरके लिये कम्युनिस्टोंको दोषी ठहराया।

उनके भाषणके बाद हर प्रान्तमें कम्युनिस्टोंकी आम गिरफ़्तारी शुरू हो गयी। बम्बई सरकारने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेसके अध्यक्ष **कॉ. डांगे,** बम्बई प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेसके अध्यक्ष **कॉ. मिरजकर,** और मज़दूर आन्दोलनके अन्य कई प्रमुख नेताओंको, जो कम्युनिस्ट पार्टीके सदस्य भी हैं, गिरफ़्तार कर लिया। अन्य प्रान्तोंमें सैकड़ों गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। कितनी ही जगह पार्टी-दफ़्तरों पर सील लगा दी गयी है। लगभग सभी प्रान्तोंमें, कहने को नहीं, परन्तु असलमें पार्टी गैरक़ानूनी कर दी गयी है।

मैं तमाम ईमानदार लोगों और जनवादियोंसे अपील करता हूँ कि वे संगठनकी स्वतंत्रता, आम जनताकी नागरिक आज़ादी और अन्यायपूर्ण मौजूदा सामाजिक व्यवस्थाके खिलाफ़ संघर्ष करनेके उसके हक़ पर जानबूझ कर किये गये इस हमलेका विरोध करें। मैं तमाम ग़ैरदली पार्टियोंसे अपील करता हूँ कि वे अन्य जनसंगठनोंके साथ मिलकर माँग करें कि यह रोक फ़ौरन वापस ली जाय, ये हमले फ़ौरन बन्द किये जायें और कम्युनिस्ट पार्टी

को संगठन, भाषण और प्रचारकी पूरी आज़ादी और स्वतंत्रता दी जाय।

इस हमलेको सही साबित करनेके लिये बंगालके गृहमंत्री श्री किरण शंकर रायने झूठ गढ़ा है और उसका प्रचार किया है। उन्होंने कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टीने हथियार इकट्ठे करनेका नारा दिया था।

परन्तु चूँकि यह एक झूठ है और इसे साबित नहीं किया जा सकता, इसलिये ज़ाहिर है, उन्होंने अपने आरोपके पक्षमें एक भी सबूत देनेकी ज़रूरत नहीं समझी। बंगालमें छापे मारे जाते समय पूरी उम्मीद की गयी थी कि ढेरों हथियार और खतरनाक पर्चे बरामद होंगे। परन्तु खूब खोज करनेके बावजूद एक भी ऐसी चीज़ न मिल सकी जिससे श्री किरणशंकर राय का आरोप सही साबित किया जा सकता।

यह समझा जा सकता है कि वह पार्टी और वह वर्ग कितना नीचे गिर गया है जिसके मंत्रियोंको तमाम जनता को धोखा देनेके लिये ऐसी शर्मनाक झूठ ईजाद करना पड़ती है और जो एक राजनीतिक पार्टी पर इसलिये हमला करते हैं क्योंकि अपनी ही जनविरोधी नीतियोंके कारण वे उसकी बढ़ती हुई शक्ति और असरको रोक नहीं सकते।

इसलिये मैं हर ईमानदार कांग्रेसजन से अपील करूँगा कि वह कांग्रेस नेताशाही अथवा श्री किरणशंकर रायसे उनके आरोपका सबूत माँगे, और नहीं तो फिर यह माँग करे कि रोक फ़ौरन हटायी जाय और वे मंत्री भी हटाये जायें जिन्होंने थैलीशाहोंके संकुचित स्वार्थोंको फ़ायदा पहुँचानेके लिये जनता द्वारा दी गयी शक्तिका दुरुपयोग किया।

मैं कांग्रेस नेताशाही और पं. नेहरू से भी यह अपील करूँगा कि कम्युनिस्ट पार्टीने हथियार इकठ्ठे करनेका नारा उठाया था, इस आरोपके समर्थनमें उनके पास जो भी सबूत हों उन्हें वह जनताके सामने रखें। जाहिर है कि कोई सबूत नहीं पेश किया जा सकता क्योंकि वह है ही नहीं; हाँ, जनतासे कह दिया जायगा कि ये राज्यकी गुप्त बातें हैं जिन्हें बताया नहीं जा सकता।

कम्युनिस्ट पार्टीपर हमला, कांग्रेस मंत्रिमण्डलोंकी साहस और निर्भीकतासे आलोचना करनेमें अकेले धारासभाओंके कम्युनिस्ट सदस्योंकी गिरफ़्तारी और कम्युनिस्ट अखबारोंके प्रकाशन पर रोक उस खतरनाक स्थितिकी सूचक हैं जो हमारे देशमें हमारी आँखोंके सामने पैदा हो रही है। यह तानाशाही राज्य,— ऐसा राज्य कायम करनेकी पहली तैयारी है जिसमें भारतकी आम जनताको कोई जनवादी अधिकार नहीं होगा, सिवाय इस अधिकारके कि वह भारतके थैलीशाहों और उनकी मालिक साम्राज्यशाहीके लिये गुलामकी तरह अपना खून पसीना एक करे।

★ कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला किया जा रहा है तो वह इसीलिये कि पार्टी भारतके उन स्वार्थी वर्गोंका साथ देनेके लिये तैयार नहीं है जो अंग्रेज-अमरीकी साम्राज्यवादियोंके साथ मिलकर अत्यंत शर्मनाक और खूनी ढंगसे देशका शोषण करना चाहते हैं, जो जनआन्दोलन की ताक़तके कारण गद्दी पर पहुँचनेके बाद अब उसी जनता पर घृणित वार करते हैं और भारतकी आजादी, साम्राज्यवादी देशोंके हाथ बेचते हैं।

★ कम्युनिस्ट पार्टीका अपराध यही रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमण्डलों और नेहरू सरकारकी स्वतंत्रता-विरोधी और विश्वास-घातक नीतियोंके असली रूपको खोल कर जनताके सामने रखना उसने अपना पवित्र कर्तव्य माना है।

★ कम्युनिस्ट पार्टीका अपराध यह रहा है कि वह "आज़ाद" सरकारके समर्थनके नामपर पूँजीपतियोंके मुनाफ़ेके लिये मज़दूरों और किसानोंके हितोंकी बलि चढ़ानेसे इनकार करती है।

★ कम्युनिस्ट पार्टीका अपराध यह है कि मौजूदा सरकारका असली रूप खोल कर रखनेके बाद उसने मज़दूरों, किसानों और मध्यवर्गी जनताकी सच्ची जनवादी सरकारकी माँग उठायी है—ऐसी सरकारकी जिसमें साम्राज्यवादके सामने आत्मसमपर्ण करने वाले पूँजीपतियोंका कोई दख़ल न हो और जो सच्ची आज़ादी, जनवाद और आर्थिक खुशहाली हासिल कर सकने वाली मेहनतकशोंकी सरकार हो।

इसी उद्देश्य के लिये कम्युनिस्ट पार्टीने, उसके सदस्योंने, जहाँ भी उन्होंने जन-आन्दोलनों अथवा जन-संगठनोंका नेतृत्व किया है, उन्होंने जनताके रहन-सहन पर कोई भी हमला बर्दाश्त करनेसे इन्कार कर दिया है। नेहरू सरकार और कांग्रेस मंत्रिमण्डल दुनिया भरमें यह ढिंढोरा पीटते नहीं थकते कि कम्युनिस्ट हड़तालें और किसानोंके संघर्ष उकसाते हैं। उनके कहनेका सही तात्पर्य यह है कि कम्युनिस्ट जनताका साथ छोड़ने और जमींदारों तथा पूँजीपतियोंके शोषणके खिलाफ़ उठते हुए संघर्षोंके साथ ग़द्दारी करनेको तैयार नहीं हैं।

कम्युनिस्ट पार्टीको अपने सदस्यों पर गर्व है—उन सदस्यों पर जिन्होंने हज़ार झूठे प्रचार और बदनामीके बावजूद जनताका साथ दिया, सरकारी क्लर्कों, स्कूलोंके अध्यापकों, कपड़ा-मज़दूरों और रेलवे मज़दूरोंका उनके आर्थिक हितोंकी लड़ाईमें साथ दिया।

कम्युनिस्ट पार्टी मेहनतकशोंको, भारतके मज़दूरों, किसानों और शोषित मध्यवर्गी जनताको विश्वास दिलाती है कि सरकार कुछ भी क्यों न करे, पार्टीके ख़िलाफ़ कैसा भी गन्दा प्रचार क्यों न किया जाय और उसका कितना भी भयंकर दमन क्यों न किया जाय, परन्तु पार्टीके सदस्य उनके वाजिब संघर्षोंका—अच्छी समाज व्यवस्था, उचित रहन-सहन, समाजवाद और राजसत्ताके लिये संघर्षोंका नेतृत्व बराबर करते रहेंगे।

इसी वीरतापूर्ण भावना और करोड़ों मेहनतकश जनताके प्रति उनकी इसी वफ़ादारीके कारण पूँजीपतियों, जमींदारों और कांग्रेस सरकारोंने कम्युनिस्टों पर वार किया है। कम्युनिस्ट पार्टीके ऊपर हमलेका सही कारण यही है कि कांग्रेस सरकारों द्वारा पूँजीपतियों और जमींदारोंका, साम्राज्यशाहीसे हाथ मिलानेवालोंका खुलेआम हितसाधन करने और मेहनतकश जनताकी आज़ादी और जनवादकी बिना हिचकिचाहट बलि चढ़ानेके रास्तेमें वह एक ज़बर्दस्त रोड़ा है।

कम्युनिस्ट पार्टीके ऊपर हमलेका सही कारण यह है कि कांग्रेस सरकार समझती है कि उनकी दिवालिया तथा स्वार्थी वर्गोंका हितसाधन करने वाली नीतियोंको भारतीय जनता अब और बर्दाश्त करनेको

तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता खुद यह समझते हैं कि उनका निकम्मापन तथा उनके अनेक मंत्रियोंकी बेईमानी और घूसख़ोरीसे स्पष्ट हो चुका है कि वे जनताको बलिका बकरा बना कर अपना उल्लू सीधा करने वाले जीव है।

> कांग्रेस नेता समझते हैं कि भारत साम्राज्यशाही, पूँजीपतियों, और जमींदारोंके लिये सोनेकी चिड़िया उस समय तक नहीं हो सकता जब तक पूरा बोझ जनताके कन्धों पर न डाला जाय; और जनता इस बोझेके अपने ऊपर डाले जानेके ख़िलाफ़ संघर्ष करेगी। इसलिये, बड़े पैमाने पर यह संघर्ष छिड़े, इससे पहले सरकार और पूँजीपति चाहते हैं कि इस बढ़ते हुए आन्दोलनके संगठित नेतृत्व, कम्युनिस्ट पार्टी को उससे अलग कर दिया जाय। इस प्रकार जनवादी आन्दोलनकी नेता होनेके कारण कम्युनिस्ट पार्टी पर हमला किया गया है।

पार्टी पर हमला कर और उसे कुचल कर कांग्रेस सरकारें तानाशाही हुकूमत क़ायम करनेकी दिशामें पहला क़दम उठा रही हैं। वास्तविकताकी कसौटीसे संयोग होते ही पं० नेहरू तथा अन्य कांग्रेस मंत्रियोंके जनवादका खोखलापन प्रगट हो गया है। उनका जनवाद इतना नाजुक है कि वह मज़दूर वर्गके अख़बार "स्वाधीनता" द्वारा झकझोरा जाना उस स्थितिमें भी सहन नहीं कर सकता जब कि पूँजीपति वर्गकी वकालत करनेके लिये सैकड़ों अख़बार मौजूद हैं। उनका जनवाद इतना नाजुक है कि उसे मजदूर वर्गकी पार्टी ग़ैर-क़ानूनी करनेकी जरूरत है, किसान संगठनोंको ग़ैर-क़ानूनी करनेकी जरूरत है, तथा किसानोंकी मीटिंगों पर रोक लगानेकी जरूरत है ताकि जमींदार-पूँजीपति गुटका शोषणका पवित्र अधिकार क़ायम रह सके। उनका जनवाद इतना कमजोर है कि वह धारासभामें एक भी ईमानदार और दृढ़ विरोधीको बर्दाश्त नहीं कर सकता; इसलिये जरूरी है कि धारासभाके कम्युनिस्टोंको जेलमें बन्द किया जाय और धारासभाके सदस्यका व्यक्तिगत सुरक्षाका हक़ पैरोंतले कुचल दिया जाय। सच यह है कि उनका जनवाद केवल थैलीशाहोंका जनवाद है, मेहनतकश जनताका नहीं।

कम्युनिस्ट पार्टीके ऊपर हमला हर प्रकारके जनवादी अन्दोलन पर हमलेकी शुरूआत है। वह भारतमें फ़ासिस्ट शासन क़ायम करनेकी दिशामें पहला क़दम है। अगर इस हमलेको बर्दाश्त किया गया तो स्वार्थी वर्गों और उनकी सरकारकी हिम्मत और भी बढ़ जायगी। वह अन्य राजनीतिक संगठनोंके नेतृत्वमें चलने वाले आन्दोलनों पर और भयंकर हमला करेगी और एक-एक करके हर विरोधी दलको कुचलेगी ताकि केवल स्वार्थी वर्गोंकी हाँ में हाँ मिलाने वाले ही रह जायें और वे बिना किसी विरोधके शासन कर सकें।

> इसलिये जो चीज़ आज दाँव पर लगी है वह है भारतकी आज़ादी, भारत का जनवाद—जनता का जनवाद। कम्युनिस्ट पार्टीको क़रीब-क़रीब पूरी तरह ग़ैर-क़ानूनी करके इसीके ख़िलाफ़ जिहाद बोला गया है। संसारके हर देशका अनुभव हमें बताता है कि जब प्रतिक्रियावाद जनवादका गला घोंटना चाहता है तो वह पहला हमला कम्युनिस्ट पार्टी पर करता है।

इसलिये यह हमला तमाम ईमानदार व्यक्तियों और जनवादियों

को ललकारता है कि वे एक साथ खड़े होकर स्वार्थी वर्गोंके भारतमें फ़ासिस्ट शासन क़ायम करनेके ख़तरेका मुक़ाबला करें।

इन स्वार्थी वर्गोंके पीछे अंग्रेज़-अमरीकी साम्राज्यवाद है जो सारे संसारमें जनवादके ख़िलाफ़ विश्व-प्रतिक्रियावादकी लड़ाईका नेतृत्व कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी पर हमलेके बाद अब विदेशी मामलोंमें अंग्रेज़-अमरीकी शक्तियोंके साथ सम्बंध और भी गहरे होंगे, भारतमें युद्ध-प्रचार होगा और भारतके स्वार्थी खुले रूपसे तथा बेशर्मीके साथ विश्व-प्रतिक्रियावादके पक्षमें जा मिलेंगे ताकि विश्व-जनवादको कुचला जाय।

जब तक स्वार्थी वर्गोंकी इस क्रान्ति-विरोधी साजिशको नहीं हराया जायगा, उस समय तक समाजवादके रास्ते पर, करोड़ों मेहनतकश जनताके जनवादके रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिये तमाम ईमानदार गरमदली शक्तियोंका यह कर्त्तव्य है कि वे एक साथ खड़ी हों और इस नये हमलेका संगठित रूपसे मुक़ाबला करें।

कुछ गरमदली नेताओंने सरकारकी कार्रवाई का जबर्दस्त विरोध किया है, इसका कम्युनिस्ट पार्टी स्वागत करती है।

परन्तु **सोशलिस्ट पार्टीके नेताओंने** जो रवैया अपनाया है उससे अधिक घृणित और विश्वासघातक चीज़ कोई दूसरी नहीं हो सकती। वे खुले आम ऐलान करते हैं कि ये कार्रवाईयाँ सुविधाके लिये हैं; वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपसे पार्टीके ख़िलाफ़ दमनकी हर कार्रवाईका समर्थन करते हैं।

ये सोशलिस्ट नेता केवल कहनेके लिये ही सोशलिस्ट हैं क्योंकि उनकी नीति से यह स्पष्ट है कि वे केवल एक और पूँजीवादी विरोधी पार्टी हैं; समाजवादकी बातें तो केवल अपने कार्यकर्ताओंको धोखेमें रखनेके लिये हैं। आज कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ दमनका समर्थन करके वे भारतमें उठते हुए फ़ासिज़्मका समर्थन कर रहे हैं। देशवासी जितनी ही जल्दी इस बातको समझ जायेंगे, उतना ही अधिक अच्छा होगा।

★ कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि तमाम ईमानदार सोशलिस्ट उसके साथ मिलकर हर जनवादी अधिकारकी इस हत्याका विरोध करें और माँग करें कि पार्टीको खुले रूपसे काम करनेका पूरा अधिकार दिया जाय।

★ कम्युनिस्ट पार्टी मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियोंके संगठनों तथा अन्य संगठनोंसे अपील करती है कि वे पार्टीकी आज़ादी हासिल करनेके लिये बराबर संघर्ष जारी रखें और सरकारको ये दमन-कार्रवाइयाँ वापस लेने पर मजबूर करके भारतके प्रतिक्रियावादको एक करारी मात दें।

★ कम्युनिस्ट पार्टी तमाम हमदर्दोंसे अपील करती है कि वे दृढ़ रहें और बिना हिचकिचाये निर्भयतापूर्वक पार्टीका साथ दें। जब शासक वर्ग पार्टीके ऊपर भयंकर हमला करता है, ऐसे ही समयमें हरेककी कूवतकी आज़माइश होती है। जिन्हें कम्युनिज़्ममें आस्था है और जो जनताकी अन्तिम विजयमें विश्वास रखते हैं उनका कर्त्तव्य है कि वे दृढ़तापूर्वक मोर्चा लें और जनताके दुश्मनोंकी बाज़ी उलटें। पार्टी अपने हमदर्दोंसे अपील करती है कि वे उसके क़ानूनी होनेकी लड़ाईको जारी रख कर सरकारी नीतिका पर्दाफ़ाश करें और जो भी व्यक्ति अथवा दलोंके लिये संभव हो, उस हर तरीक़ेसे पार्टी की मदद करें।

★ पार्टीके सदस्योंसे मुझे केवल यह कहना है कि हर पार्टी-सदस्यका यह कर्तव्य है कि वह अपनेको अपनी पार्टी के और जिस अन्तरराष्ट्रीय आन्दोलनके हम अंग हैं उसके योग्य साबित करे। यह हमारे लिये गर्वकी बात है कि भारतकी जनवादकी लड़ाईमें, भारतकी समाजवाद की लड़ाईमें पहला हमला हमारे ऊपर हुआ है। हमारे लिये पीछे हटनेका सवाल नहीं उठता। हम अपनी राजनीतिको काट-छाँट कर थैलीशाहोंकी नाज़ुक-पसन्द के मुताबिक नहीं ढाल सकते। हमें लड़ते जाना है। हमें जनताका नेतृत्व करते जाना है। हममेंसे हरेकको यह विश्वास रखना चाहिये कि हम सफलतापूर्वक नेतृत्व करेंगे और जनताके सच्चे जनतंत्र, समाजवाद और मज़दूरों, किसानों तथा मेहनतकश मध्यवर्गी जनताकी जनवादी सरकार क़ायम करनेका अपना उद्देश्य पूरा करेंगे। हरेकको अपने मोर्चे पर जमे रहना है, अपना काम करते जाना है और जितनी तेज़ीसे सरकार सदस्यों को जेलके भीतर ले जाये उससे भी कहीं अधिक तेज़ीसे जनताको पार्टीके भीतर लाना है। मेहनतकशोंको यह ध्यानमें रखना चाहिये कि कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाकों की पार्टी है, जनताकी पार्टी है—लड़ने वाली करोड़ों जनताकी पार्टी है।

★

हथियार इकट्ठे करने का आरोप एक धोखे की टट्टी !

दिल्लीमें राष्ट्रीय सप्ताहके उद्घाटनके समय दिये गये अपने भाषणमें पं० नेहरूने पश्चिमी बंगालमें कम्युनिस्ट पार्टीके ग़ैरक़ानूनी किये जाने और अन्य प्रान्तोंमें भी उसके क़रीब-क़रीब ग़ैरक़ानूनी किये जानेको उचित ठहरानेकी जो कोशिश की है वह एक आश्चर्यजनक कलाबाज़ी है।

जनवादके सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे देखने पर स्पष्ट है कि दबी-कुचली जनताकी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीका गैर-क़ानूनी किया जाना एक राजनीतिक संगठनकी आज़ादी पर खुला हमला है। और इसलिये इस कार्रवाईको करने वाली सरकारके लिये यह लाजिमी है कि वह अपने द्वारा उठाये गये क़दमके लिये सच्चे और गंभीर कारण बताये।

भारतीय संघके प्रधान मंत्री होनेके नाते पं. नेहरूका यह कर्तव्य था कि वह कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ लगाये गये आरोपोंको साबित करते। साथ ही यह साबित करना भी उनका कर्तव्य था कि पार्टी करोड़ों मेहनतकश जनताके हितोंके ख़िलाफ़ षड़यंत्र रच रही थी और शोषकोंके स्वार्थोंकी अलमबरदार बन रही थी—क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ की गयी किसी कार्रवाईको केवल इसी आधार पर उचित ठहराया जा सकता था।

पं. नेहरूने अपने भाषणमें ऐसा कोई प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने बंगाल सरकारके पार्टीको गैरक़ानूनी करनेके फ़रमानको उचित बताया और उसका समर्थन किया; पर साथ ही उसकी कोई जिम्मेदारी स्वीकार करनेसे भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टीको गैरक़ानूनी करनेका बंगाल सरकारका फ़ैसला एक स्वतंत्र फ़ैसला है और इस सवाल पर केन्द्रसे कोई विशेष सलाह नहीं ली गयी थी।

परन्तु सचाई शायद यह है कि जहाँ एक ओर केन्द्रीय सरकारने पश्चिमी बंगाल सरकारको अपनी मर्ज़ीके मुताबिक कार्रवाई करनेकी आज़ादी दे दी थी वहाँ दूसरी ओर हथियार इकट्ठे करनेकी झूठी, गढ़ी गयी कहानीमें उसे विश्वास नहीं था। कमसे कम पं० नेहरूने केन्द्रीय सरकारकी ओरसे इस कहानीका समर्थन नहीं किया है। अपने भाषणमें उन्होंने कहा, "एक बड़े पैमाने पर हथियार इकठ्ठे किये जा रहे थे, सरकारको हिंसात्मक साधनोंसे उलटनेकी तैयारी की जा रही थी और सिक्योरिटी सर्विसेज़को शक्तिहीन बना देनेका ज़बर्दस्त ख़तरा पेश हो गया था। पश्चिमी बंगाल सरकारके पास इन सब आरोपोंको साबित करनेके लिये सबूत मौजूद था और इसलिये उसने कम्युनिस्ट पार्टीको गैरक़ानूनी करनेका आख़िरी हथियार इस्तेमाल किया।"

यदि पश्चिमी बंगाल सरकारके पास सबूत था तो केन्द्रीय सरकारके पास भी कोई सबूत क्यों नहीं था? ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारतव्यापी मामलोंकी किसी भी प्रान्तीय सरकारसे ज़्यादा केन्द्रीय सरकारको ख़बर होती है—परन्तु पं० नेहरूने स्पष्ट शब्दोंमें यह दावा नहीं किया कि केन्द्रीय सरकारके पास ऐसा कोई सबूत है। अगर उसके पास सबूत होता तो इसमें सन्देह नहीं कि उसने सभी प्रान्तों और रियासतोंमें कम्युनिस्ट पार्टीको ग़ैरक़ानूनी करनेका आम हुक्म ज़ारी कर दिया होता और उस कार्रवाईकी पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार की होती। इसके विपरीत जब पं. नेहरूने दिल्लीके कम्युनिस्टोंकी गिरफ़्तारीके बारेमें डोमिनियन पार्लियामेंट में बयान दिया तो उन्होंने हथियार इकट्ठे करनेका कोई ज़िक्र नहीं किया और यही नहीं, उन्होंने केवल मात्र यह कहकर संतोष कर लिया कि "सिक्योरिटी सर्विसों तथा इसी तरहकी अन्य सर्विसों के दृष्टिकोणसे सरकारने इस समय ऐसी कार्रवाई न करना कुछ ख़तरनाक समझा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किरणशंकर रायने हथियार इकट्ठे करनेकी जो कहानी गढ़ी है उसमें न तो पं. नेहरू विश्वास करते हैं और न वह उस पर अमल करते हैं। वह स्वयं केवल सिक्योरिटी सर्विसोंकी बातें करते हैं परन्तु साथ ही जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि इसे साबित करनेके लिये पश्चिमी बंगाल सरकारके पास काफ़ी सबूत था।

कम्युनिस्ट पार्टी सरकारको उलटनेके लिये हथियार इकट्ठे करनेकी तैयारी कर रही थी, इस गढ़े हुए आरोपकी झूठ स्पष्ट हो जाती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार तक इस षड्यंत्रसे परिचित दिखायी नहीं पड़ती।

कमसे कम पं. नेहरू इसके बारेमें किसी व्यक्तिगत अथवा प्रत्यक्ष जानकारीका दावा नहीं करते। इससे केवल एक ही नतीजे पर पहुँचा जा सकता है, और वह यह कि बिना किसी कारणके और केवल जनताको धोखा देनेके लिये पार्टीको सरकारके उलटनेका षड्यंत्र रचनेका दोषी बता कर एक राजनीतिक पार्टीके ऊपर भयंकर हमला बोला गया है।

पं. नेहरूसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अन्य प्रान्तीय सरकारोंने किस आधार पर कार्रवाई की और मैसूर तथा इन्दौर जैसी रियासतोंने, जिन्होंने केवल कम्युनिस्ट पार्टीको ही नहीं बल्कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेससे सम्बंधित मजदूर सभाओंको भी गैरक़ानूनी क़रार दे दिया है, किस आधार पर कार्रवाई की। क्या बम्बई, मद्रास, मध्यप्रान्त और रियासतोंके मजदूर वर्गके प्रमुख नेताओंकी आम गिरफ़्तारीका आधार भी यही था कि कम्युनिस्ट पार्टीने सरकारको उलटनेके लिये हथियार इकट्ठे करनेका नारा बुलन्द किया था? क्या इन सब सरकारोंके पास वे सबूत हैं जो कि, मालूम पड़ता है केन्द्रीय सरकारके पास नहीं हैं। और क्या वे भी बिना केन्द्रीय सरकारसे सलाह-मशविरा किये स्वतंत्र कार्रवाइयाँ करती हैं?

क्या पं. नेहरू इस बातकी भी जाँच करेंगे कि पश्चिमी बंगाल सरकारके हुक्म द्वारा बन्द किये गये अख़बार "स्वाधीनता" ने हथियार इकट्ठे करनेका कहीं नारा तो

नहीं उठाया था और कहीं मलयाली अखबार "देशाभिमानी" ने भी हथियारबन्द होने के लिये उसी तरह आहवान तो नहीं किया था? क्या पं. नेहरू इस बातकी भी जाँच करेंगे कि क्या धारासभाओंके विरोधी कम्युनिस्ट सदस्य का. डांगे और का. ज्योति बसु इसी कारण गिरफ़्तार किये गये हैं कि वे भी सरकारको उलटनेके लिये हथियार इकठ्ठे करनेके षडयंत्रमें शामिल थे!

या हथियार इकट्ठे करनेका बहाना कम्युनिस्ट पार्टीके नेतृत्वमें चलने वाले तमाम जन-संगठनों पर वार करनेके लिये एक धोखेकी टट्टी था जो इस आशा से किया गया था कि इस दमनके बाद सरकार द्वारा चलायी गयी प्रतिक्रियावादी नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेसका मज़दूरोंके नाम पर बोल सकना संभव हो जायगा और इस तरह मज़दूर-वर्गको कुचलनेका काम आसान हो जायगा। जिस समय अडोल्फ हिटलरने कम्युनिस्टों पर राइख़स्टागमें आग लगानेका आरोप लगाया था, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट दोनों मज़दूर सभाओंका दमन किया था और मज़दूर वर्गके संगठन पर नहीं, बल्कि उसके ख़िलाफ़ जारी किये गये आतंक पर आधारित लेबर फ्रन्ट क़ायम किया था, उस समय उसने ठीक यही तरीक़े अख्तियार किये थे।

मैं अपनी माँग फिर दुहराता हूँ कि अगर केन्द्रीय सरकार अथवा किसी प्रान्तीय सरकारके पास हथियार इकठ्ठे किये जाने की बाबत सबूत मौजूद है तो वह उसे प्रकाशित करे और उस पर जनताको फ़ैसला देने दे। कांग्रेस मंत्रिमण्डल और पं. नेहरूने राज्यकी गुप्त बातोंको गुप्त रखने के नामपर अथवा यह कहकर कि उनका प्रकाशित करना जनताके हितमें नहीं होगा इस तथाकथित सबूतको अपने ही तक सीमित रखनेकी जो कोशिश की है, उससे पता चलता है कि आज कांग्रेस मंत्रिमण्डल भी जनतासे उतना ही डरते हैं जितना कि पुरानी ब्रिटिश सरकार डरती थी। पुरानी सरकार जानती थी कि उसके सबूत जनवादकी कसौटी पर कभी खरे न उतरेंगे और उसे डर था कि अगर उसने क्रान्तिकारियोंके अथवा उनकी कार्रवाईकी योजनाओंके बारेमें पूरा सबूत जनताके सामने रखा गया तो उन योजनाओं को जनता कहीं अपना न ले। परन्तु जो सरकार यह दावा करती है कि उसके पीछे जनताका समर्थन है उसे तो चाहिये कि वह निर्भीक होकर तमाम सबूत जनताके सामने रखे और उसे फ़ैसला करने दे। ऐसा करनेसे इन्कार करनेका केवल यही मतलब है कि पहले तो षड्यंत्रके सम्बंधमें उसके पास कोई सबूत नहीं है; दूसरे, उसे डर है कि अगर उसने कम्युनिस्टोंकी योजनाओंको प्रकाशित किया तो जनता उनकी ओर आकर्षित होगी।

जब तक सरकार अपना सबूत प्रकाशित नहीं करती उस समय तक जनता यही मानेगी कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और, सरकार केवल कम्युनिस्ट पार्टीका दमन कर रही है।

दूसरी बात यह है कि बहुमतके समर्थन का दावा करनेवाली कांग्रेस सरकारें साधारण क़ानूनको क्यों नहीं मानतीं और अदालत से फ़ैसला हासिल क्यों नहीं करतीं? वे अखबारों का मुँह बन्द करने और बिना मुक़दमा चलाये नज़रबन्द करनेका पुराना साम्राज्यवादी अत्या-

चारी तरीक़ा क्यों अख्तियार करती है ?— ये अधिकार तो साम्राज्यवादी सरकारने आम तौर पर लड़ाईके जमानेमें इस्तेमाल किये थे, परन्तु आज तमाम कांग्रेस सरकारें उनका उस समय इस्तेमाल कर रही हैं जब लड़ाई नहीं हो रही है !

सरकारके पास सबूत नहीं

अदालतके फ़ैसलेका सामना करनेसे इन्कार करनेपर एक बार फिर सरकार का भाण्डा फूट जाता है क्योंकि उससे पता चलता है कि खुली अदालतमें वह जनवादके किसी भी सिद्धान्तके अनुसार कम्युनिस्टोंको सज़ा नहीं दे सकती। स्वयं क़ानूनका ही दमन करके वह उनका दमन कर सकती है।

आख़िर केन्द्रीय सरकार कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ खुले हमलेको क्यों वाजिब समझती है ? इसका कोई भी कारण न बताते हुए पं. नेहरूने एक ऐसा झूठा तर्क खोज निकाला है जिसे मस्तिष्क की कैसी भी दौड़ानसे ईमानदारीका नहीं कहा जा सकता ! उन्होंने कहा है, " भारत संघके प्रान्तोंको बहुत काफ़ी आज़ादी है और वे जिस तरह अपने लिये अच्छा समझते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार उन्हें सलाह दे सकती है परन्तु वह इस स्थितिमें नहीं है कि अपनी मर्ज़ी उनके ऊपर लाद सके। केन्द्रीय सरकार यह नहीं चाहती कि किसी भी विशेष सवालके सम्बंध में प्रान्तों पर दबाव डाला जाय क्योंकि वैसा करनेसे उस मामलेकी जिम्मेदारी उसके कन्धोंपर आ जाती है। "

अर्थात, प्रान्तोंकी आज़ादीका मतलब है उन्हें जनताके बुनियादी अधिकार कुचलने, उसके जनवादी अधिकारों पर हमला करने और फ़ासिस्ट आतंकका राज्य क़ायम करने की खुली छूट। प्रान्तकी आज़ादीकी यह एक आश्चर्यजनक परिभाषा है। क्या इसके मातहत प्रान्तोंको यह अधिकार भी मिलता है कि वे ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवादियों अथवा फ़ासिस्टोंके साथ मिलकर षड्यंत्र रच सकें और उन बुनियादी जनवादी अधिकारोंको कुचल सकें जिनको मौजूदा राज्य अथवा मौजूदा कांग्रेस कार्यक्रमके मातहत सम्पूर्ण भारतमें स्वीकार किया जाता है ? प्रान्तकी आज़ादीका यह मतलब नहीं हो सकता कि प्रान्त उन बुनियादी सिद्धान्तोंको ही ठुकरा दें जिनके आधार पर भारतीय जनवादका ढाँचा निर्भर समझा जाता है। प्रान्तकी आज़ादीका पं. नेहरूका बहाना एकदम थोथा है। यह दलील उस साम्राज्यवादी गृह-मंत्रीकी याद दिला देती है जिसने दमनकी जिम्मेदारीको ख़ुद स्वीकार कर सकनेके साहसके अभावमें प्रान्तों पर टरका दिया था और जनता की आवाज़को चुप करनेकी कोशिश की थी।

जनवादके बुनियादी सिद्धान्तोंको बलायेताक़ रखे बग़ैर अगर कोई प्रान्तीय सरकार शासन नहीं चला सकती तो उसे हटना होगा; उसे क़ायम नहीं रहने दिया जा सकता। और अगर भारत संघकी सरकार इस अथवा उस प्रान्तकी फ़ासिस्ट कार्रवाइयोंके ख़िलाफ़ दख़ल नहीं दे सकती तो उस सरकारको भी क़ायम रहनेका कोई अधिकार नहीं है।

पं. नेहरू कहते हैं कि "कम्युनिस्ट जनताके बीच बेचैनी पैदा करने और देशमें अराजकता फैलाकर सत्ता पर क़ब्ज़ा करनेका इरादा कर रहे थे।" इस वाक्यकी ध्वनि ठीक उसी तरहकी

है जैसी मेरठ-षड़यंत्र केसमें साम्राज्यवादी वकील लैंग्फ़ोर्ड जेम्सके आरोप लगाने वाले भाषणकी थी जिसने कम्युनिस्टोंके ख़िलाफ़ इसी तरहके आरोप लगाये थे।

पं. नेहरूको मालूम है कि साम्प्रदायिक दंगोंके कारण देशमें काफ़ी अराजकता थी और दिल्लीमें तो महीनों अराजकताके सिवा कुछ था ही नहीं; और अगर कम्युनिस्ट सचमुच समझते थे कि अराजकताके ज़रिये सत्तापर क़ब्ज़ा किया जा सकता है तो वह उनके लिये स्वर्ण अवसर था। परन्तु फिर भी साम्प्रदायिक दंगोंके कारण पैदा हुई घोर अराजकताके दौरानमें यह कम्युनिस्ट ही थे जो उस समय भी शान्ति और साम्प्रदायिक सद्भावनाके लिये लगातार जमकर प्रचार करते रहे जिस समय लगता था कि पं० नेहरू भी अपनी हिम्मत छोड़ बैठे हैं।

इस समय पं. नेहरू केवल वही साम्राज्यवादी झूठ दुहरा रहे हैं जिसके अनुसार क्रान्तिकारी जनताका हर आन्दोलन गड़बड़ी और अराजकता होता है। वह फ़ैक्टरियोंकी हड़तालों और मजदूर हलचलोंकी ओर उँगली उठाते हैं और कहते हैं कि वे सिक्योरिटी सर्विसोंके लिये जबर्दस्त ख़तरा हैं। यह उसी शोषित और दबी-कुचली जनताका आन्दोलन है जिसके बारेमें पं. नेहरूने एक समय बड़े जोशके साथ लिखा था और जिसकी भूख और ग़रीबीके कारण उन्होंने अपने गुस्सेका इज़हार किया था। आज उसी आन्दोलनका कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व कर रही है और पं. नेहरू उसको अराजकता और गड़बड़ीका नाम देते हैं। ईमानदारीके साथ पं. नेहरूको यह समझना चाहिये कि हड़तालें पिछले तीन-चार वर्षोंसे लगातार होती आ रही हैं और फलती जा रही हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति ख़राब है। और, अगर आज सिक्योरिटी सर्विसों और सरकारी कर्मचारियों तक पर उनका असर होता है तो इसलिये कि नेहरू-सरकारने उनकी दशा सुधारनेके लिये कुछ नहीं किया और क्योंकि वह निकट भविष्यमें ही आम छँटनी करनेकी योजना बना रही है।

जिस वजहने नेहरू सरकारको मजदूर वर्गकी तथा अपने ही कर्मचारियोंकी माँगें माननेसे रोक दिया है वह है पूँजीपतियोंके हितोंके आगे उसका पूर्ण आत्मसमर्पण।

हड़तालें उस समय तक और भी होती जायेंगी और सर्विसोंमें और भी असंतोष होगा जब तक कि सरकार उनकी माँगें स्वीकार नहीं करेगी और पूँजीपतियोंके मुनाफ़ेकी ख़ातिर उनकी बलि चढ़ानेकी अपनी नीति नहीं त्यागेगी। हड़तालोंके लिये कम्युनिस्टोंको ज़िम्मेदार ठहराना और यह बतानेकी कोशिश करना कि कम्युनिस्ट बनावटी असंतोष पैदा कर रहे हैं पूँजीपतियोंके बरसों पुराने झूठका प्रचार करना है। कम्युनिस्ट सरकारी कर्मचारियों समेत आम जनताके हितोंकी रक्षा ज़रूर करेंगे।

साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टीने राष्ट्रीकरण, जीने लायक तनख़ा आदिका रचनात्मक कार्यक्रम भी पेश किया है जिसकी कमसे कम कुछ बातोंको फ़ौरन अमलमें लाया जा सकता है और जिनसे देशकी आर्थिक स्थिति सुधर जायगी। परन्तु नेहरू सरकार तो पूँजीवादी व्यवस्था क़ायम रखनेकी वेदीपर जनताकी आवश्यकताओंकी बलि चढ़ाना चाहती है। वह इस कार्यक्रमको अमलमें नहीं लायेगी। इसीलिये वह हर जगह हड़तालोंको उकसावा देती

है और उनके लिये कम्युनिस्टोंको जिम्मेदार ठहराकर उन्हें संकोचरहित होकर दबाना संभव बनाना चाहती है।

हड़तालें लाज़िमी हैं

> एक बच्चा भी यह समझता है कि ये हड़तालें और आर्थिक असंतोष पूँजीवादी समाजके सबसे बड़े संकट का परिणाम हैं। यह संकट ब्रिटेन और अमरीकामें फूट रहा है और इसके कारण सारी पूँजीवादी दुनियामें हड़तालों की लहर दौड़ रही है।

इसे हल करनेके दो रास्ते हैं: एक रास्ता पूँजीपतियोंके हाथसे आर्थिक सत्ता छीन लेनेका रास्ता है जो जनताके हितमें है; दूसरा रास्ता पूँजीपतियोंकी सत्ता क़ायम रखनेका रास्ता है जिसका मतलब जनताको कुचलना है। नेहरू सरकार दूसरे तरीक़ेसे संकटको हल करनेकी कोशिश कर रही है। इसलिये उसकी मुखालफ़त हमारे देशकी करोड़ों जनतासे होती है—और वह ख़याल करती है कि उसके ख़िलाफ़ षड़यंत्र रचा जा रहा है।

पं. नेहरू कहते हैं कि "केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय, किसी भी सरकारका कम्युनिस्टों अथवा किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टीको अपने विचारोंका प्रचार करने और जनताको अपने साथ लानेकी कोशिश करनेसे रोकनेका कोई भी इरादा नहीं है।" यह आश्वासन कितना हवाई और पाखण्डपूर्ण है, यह इसी बातसे समझा जा सकता है कि जब जनता जिन्दा रहनेके लिये जिन्दगी और मौतकी लड़ाईमें जूझ रही है उस समय सरकार यही नहीं कि उसके लिये कुछ कर नहीं रही है बल्कि वह गरीबी और शोषणको और भी बढ़ा रही है। कम्युनिस्टोंको जो कथित आज़ादी है, उसकी छत्रछायाके नीचे जनताके संघर्षोंका संगठन करने, हड़तालोंका नेतृत्व करने और जनताकी फ़ौरी मांगें हासिल करने के लिये सरकार अथवा स्वार्थी वर्गों पर जन-संगठनोंका पूरा दबाव डालनेकी स्वतंत्रता तक उन्हें नहीं है। अगर हम इनमेंसे कोई भी काम करते हैं तो वह सिक्योरिटी सर्विसोंके लिये खतरनाक है!

> हम अपने विचारोंका शायद केवल धनियोंके ड्राइंग-रूमोंमें ही प्रचार कर सकते हैं, मज़दूरोंके आगे नहीं। हमको मज़दूरोंके सामने समाजवादकी बात नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे वे उनके लिये संघर्ष शुरू कर देंगे। संक्षेपमें जनवादके बारेमें पं. नेहरूका विचार है कि अगले चुनाव आन्दोलन तक इन्तज़ार करो। उस समय तक जनताके हितोंकी रक्षा करने अथवा सरकारकी जन विरोधी नीतियोंसे लोहा लेनेकी कोई कोशिश मत करो। अगर तुम यह करते हो तो यह हिंसा है।
>
> उस समय तक जनवादका कोई अर्थ नहीं जब तक कि जनताको सरकारकी जन-विरोधी नीतियोंके ख़िलाफ़ अपना दबाव डालने की, अपने रहन-सहनके स्टैण्डर्ड की रक्षा करनेकी और अगर सरकार उनकी माँगें नहीं मानती तो उस सरकारको आमूल बदल डालनेकी पूरी आज़ादी न हो। जनवादका सार तत्व यही है। और यही वह चीज़ है जिसका गला घोंटा जा रहा है।

पं० नेहरू काफ़ी सिरदर्द कर यह दिखानेकी कोशिश करते हैं कि कम्युनिस्ट

पार्टीके खिलाफ़ हमला एकदम घरेलू मामला है और उसका अन्तरराष्ट्रीय राजनीतिमें भारतके रुख़से कोई सम्बंध नहीं है। परन्तु यह संभव नहीं कि कोई स्वदेशमें जनवाद-विरोधी अथवा फ़ासिस्ट हो और बाहर जनवादी। पं. नेहरूको कमसे कम यह समझना चाहिये कि अगर मज़दूर आन्दोलनके दमनकी नीति स्वदेशमें जारी है तो यह लाज़िमी है कि अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्रमें भी उसका मज़दूर विरोधी और जनवाद-विरोधी शक्तियोंके साथ सम्बंध जुड़े। मज़दूर वर्गके दमन की नीतिका यह आवश्यक उद्देश्य होता है कि पूँजीपतियों और पूँजीवादकी रक्षा की जाय और संसारव्यापी पैमाने पर यह उसी समय संभव है जब साम्राज्यवादी शक्तियोंका साथी बना जाय। एक जमाना था जब पं. नेहरू समझते थे कि जनवादकी रक्षाकी लड़ाई एक है, उसे बाँटा नहीं जा सकता।

साम्राज्यवादियोंके साथ गठबंधन

बहरहाल, क्या यह केवल अकस्मात हुआ है कि कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ हमलेके साथ ही साथ पं. नेहरू और उनकी सरकार ने भारतीय पूँजीपतियोंको आश्वासन दिया है कि राष्ट्रीकरण नहीं होगा और विदेशी पूँजीपतियोंको आश्वासन दिया है कि किन्हीं स्थितियोंमें उन्हें अपने द्वारा चालू किये गये उद्योगों पर पूरा कण्ट्रोल हासिल करने दिया जायगा। हवाना समझौतेके ज़रिये साम्राज्यवादी शक्तियोंके साथ जो आर्थिक सम्बंध जोड़े गये हैं, हालमें औद्योगिक नीतिवाले प्रस्तावमें भारतीय और विदेशी पूँजीपतियोंको जो आश्वासन दिये गये हैं, वे सब इस बातका अकाट्य प्रमाण हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियोंके साथ आर्थिक सम्बंध जुड़ रहे हैं और आर्थिक गठ-बंधन क़रीब-क़रीब हो चुका है।

विदेशी पूँजीको उस समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि मज़दूर वर्गको दबाया न जाय और पूँजीको सुरक्षा, स्थायित्व और मुनाफ़ेकी गारंटी न दी जाय। हवाना व्यापारिक समझौतेका स्वाभाविक परिणाम और विदेशी तथा देशी पूँजीपतियोंको दिये गये आश्वासनोंका ही दूसरा पहलू कम्युनिस्ट पार्टी और हड़ताल आन्दोलनके ख़िलाफ़ हमला है। जो भी देश आर्थिक रूपसे एक पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है वह राजनीतिक रूपसे दूसरे पक्षमें नहीं हो सकता। पं. नेहरूको यह समझना चाहिये कि उनकी सरकार द्वारा बरती जाने वाली आर्थिक नीति उसे अंग्रेज़-अमरीकी साम्राज्यवादियोंके रथके पहियेके साथ बांध चुकी है; उसकी तटस्थताकी बातें भारतको अंग्रेज़ अमरीकी पक्षमें आर्थिक और राजनीतिक रूपसे खींचने वालोंकी साजिशोंको छिपाने की नक़ाब मात्र हैं।

कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ जो हमला बोला गया है वह इसी साजिश का अंग है और अगर आज पं. नेहरू हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह केवल एक घरेलू मामला है तो उससे कोई भी समझदार आदमी धोखेमें नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले साम्राज्यवादी देशोंके साथ आर्थिक समझौते हो चुके हैं और उन्हींके आधार पर अब आगे राजनीतिक समझौते होंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ हमलेको जन-विरोधी स्वार्थी वर्गोंने उभाड़ा है और उस पर अमल किया है उन प्रान्तीय मंत्रि मण्डलों और केन्द्रीय सरकारने जिनमें उनकी ही तूती बोलती है और जो उनके आगे घुटने टेकती हैं।

प्रतिक्रियावादकी जड़ें न जमने दो

पार्टीने हथियार इकट्ठे करनेका आह्वान किया था, यह झूठ गढ़ कर पश्चिमी बंगाल सरकार केवल यह चाहती थी कि जनताको धोखा देकर जनता और उसके जनवादी अधिकारोंके ख़िलाफ़ इस भयंकर हमलेको उसके गलेके नीचे उतार दिया जाय। अन्य प्रान्तीय सरकारोंने कुछ कहना ही जरूरी नहीं समझा और इस बातकी आशा की कि कांग्रेसकी प्रतिष्ठा और पं. नेहरूका बयान जनताको ठण्डा करनेके लिये काफ़ी साबित होगा।

यह हमला मज़दूरों, किसानों, मध्यवर्गी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियोंको कुचलने और जनवादी आन्दोलनको दमनकी आग में भस्म कर देनेका भारतके क्रान्ति विरोधी स्वार्थी वर्गोंका समझा-बूझा षड़यंत्र है। यह केवल कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ ही नहीं, पूरे जनवादी आन्दोलनके ख़िलाफ़ ज़िहाद है।

अब, जब कि यह स्पष्ट हो गया है कि इस कथित 'हथियार इकट्ठे करने'से केन्द्रीय सरकार तक परिचित नहीं थी; तब यह तमाम नागरिकों, तमाम साम्राज्य-विरोधी शक्तियोंका कर्त्तव्य है कि वे पश्चिमी बंगाल सरकारसे इस आरोपको साबित करनेके लिये सबूतकी मांग करें, तमाम कम्युनिस्ट नेताओंकी रिहाई की मांग करें, गैरक़ानूनी करनेके हुक्म और तमाम दमनकारी हुक्मोंको रद्द करनेकी मांग करें। जनताको अपने जनवादी अधिकारोंकी रक्षाके लिये एक जबर्दस्त आन्दोलन छेड़ना है ताकि प्रतिक्रियावाद मजबूत न होने पाये और उसकी जड़ें जमने न पायें।

हमें आन्दोलन छेड़ना है और माँग करनी है कि हालमें बने तमाम जन-सुरक्षा क़ानून, जो सरकारका साधारण क़ानूनको ठुकरा कर कार्रवाई करना संभव बनाते हैं, वापस लिये जायें; किसीको बिना मुक़दमा चलाये नजरबन्द न किया जाय और यह कि जनताकी राजनीतिक पार्टियों को मंत्रिगण इतनी आसानीसे गैर-क़ानूनी क़रार नहीं दे सकते।

आम जनताका यह कर्त्तव्य है कि वह सरकारको साफ़ शब्दोंमें बताये कि सरकारकी सुरक्षाके नाम पर ताक़तका इस्तेमाल उस समयतक बर्दाश्त नहीं किया जायगा जब तक कि उसका इस्तेमाल शोषक वर्गोंको दबाने और शोषित वर्गोंके हितोंकी रक्षा करनेके लिये नहीं किया जाता।

पं. नेहरूके भाषणसे तमाम समझदार नागरिकोंको विश्वास हो जाना चाहिये कि कम्युनिस्ट पार्टीके ख़िलाफ़ हमला किसी तरह न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, खुद पं० नेहरू भी उसका औचित्य नहीं बता पाये हैं; और इसलिये तमाम जनता, तमाम नागरिकों और तमाम जनसंगठनोंकी संयुक्त शक्तिसे इसको हराना चाहिये।

★

दमनके कुछ उदाहरण

● संस्थायें जो ग़ैरकानूनी कर दी गयी हैं
● दफ़्तर जिन पर सीलें ठोंक दी गयी हैं

बंगाल : कम्युनिस्ट पार्टी तथा उसके नेतृत्वमें चलने वाले संगठन। दफ़्तर पर सील लगा दी गयी है। प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओंके मकानों पर ताला जड़ दिया गया है। मकानमें रहनेवाली औरतों तथा बच्चोंको कुछ ही मिनटमें मकान ख़ाली करने पर मजबूर किया गया।

मैसूर : कम्युनिस्ट पार्टी ग़ैरक़ानूनी घोषित।

इन्दौर : कम्युनिस्ट पार्टी तथा अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेससे सम्बंधित सभी यूनियनें ग़ैरक़ानूनी घोषित।

चन्द्रनगर : कम्युनिस्ट पार्टी ग़ैरक़ानूनी घोषित।

दिल्ली : कम्युनिस्ट पार्टीके दफ्तरों पर तालाबन्दी।

पूर्वी पंजाब : कम्युनिस्ट पार्टीके दफ़्तर तथा बहुतसी मज़दूर सभाओंके दफ़्तरों पर सील जड़ दी गयी।

● अख़बार जिन पर रोक लगायी गयी है

स्वाधीनता : पश्चिमी बंगालकी कम्युनिस्ट पार्टीका दैनिक।

देशाभिमानी : केरालाकी कम्युनिस्ट पार्टीका दैनिक।

प्रजाशक्ति : आन्ध्र कम्नुनिस्ट पार्टीका दैनिक।

● पुलिसके छापे और तलाशियाँ

बम्बई : कम्युनिस्ट पार्टी का केन्द्रीय दफ्तर, कम्युनिस्ट पार्टीकी बम्बई कमिटीका दफ़्तर, गिरणी कामगार यूनियन का दफ़्तर, अनेकों प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओंके मकान।

मद्रास : तामिलनाडकी कम्युनिस्ट पार्टीका दफ़्तर, कम्युनिस्ट पार्टीकी ज़िला कमिटीका दफ़्तर, मद्रासकी प्रन्तीय ट्रे. यू. कांग्रेसका दफ़्तर, प्रान्तीय किसान सभाका दफ़्तर, विद्यार्थी संघका दफ़्तर, जनशक्ति-प्रेस, नेहरू-प्रेस, चमड़ा मज़दूर यूनियनका दफ़्तर; प्रान्त भरमें कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड यूनियनों, और किसान सभाओंके दफ़्तर।

पटना : बिहार की कम्युनिस्ट पार्टीके दैनिक पत्र **जनशक्ति** का दफ़्तर। पटना, गिरिडीह, मुज़फ़्फ़रपुर, हाजीपुर, लखीसराय, दरभंगा, भागलपुर, बेतिया,

मोतीहारी, समस्तीपुर, जमालपुर, आदि-आदि स्थानोंपर प्रान्त भरमें पुलिसके छापे ।

इलाहाबाद : कम्युनिस्ट पार्टीका दफ़्तर ।

पूर्वी पंजाब : प्रान्त भरमें पुलिसके छापे ।

शोलापूर : लाल बावटा कामगार यूनियन, हतमार कामगार संघ, बीड़ी कामगार संघके दफ़्तर।

गुन्तूर : प्रान्तीय कम्युनिस्ट पार्टीका दफ़्तर, गाड़ी ढोनेवालोंका दफ़्तर, "नवयुग" का दफ़्तर, प्रेस-वर्कर्स यूनियनका दफ़्तर ।

त्रिचनापल्ली : गोल्डन रॉकमें कम्युनिस्ट पार्टीका दफ़्तर, लेबर यूनियनका दफ़्तर कम्यून और का० आनन्दन नम्बियारका मकान ।

नागपुर : जी. आई. पी. रेलवेमेन्स यूनियनका दफ़्तर, ५०६ कमाण्ड-वर्कर्स यूनियन का दफ़्तर। यहाँ **"हितवाद"** दैनिकके दफ़्तर पर भी पुलिसने छापा मार यद्यपि अख़बार कम्युनिस्ट पार्टीसे सम्बंधित नहीं है ।

अजमेर : कम्युनिस्ट पार्टीका दफ़्तर ।

● गिरफ़्तारियाँ

बंगाल : कॉ. मुज़फ़्फ़र अहमद—कम्युनिस्ट पार्टीकी नींव डालनेवाले पार्टी सदस्य । कॉ. ज्योति बसु--बंगालकी धारासभाके सदस्य; अ. भा. रेल्वेमेन्स फ़ेडरेशनके उप-सभापति । कॉ. अरुण बोस, विश्वनाथ मुकर्जी तथा मज़दूर सभा और किसानोंके अनेकों नेता ।

बम्बई : कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे—बंबईकी धारासभाके सदस्य, अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेसके अध्यक्ष, विश्व ट्रेड यूनियन संघकी कार्यकारीणीके सदस्य ।
कॉ. मिरजकर--बम्बई कारपोरेशनके मेम्बर (तीसरी बार चुने गये) ।
कॉ. बैजनाथ सिंह :—बी. बी. एण्ड सी. आई रेलवे मज़दूरोंके प्रमुख नेता ।
कॉ. सैमुअल आगस्टीन:—एच. एम. आई डॉकयार्ड वर्कर्स यूनियनके सभापति ।
कॉ. देशपाण्डे:—उपरोक्त यूनियनके कोषाध्यक्ष ।

कॉ. प्रीतम सिंह :— उपरोक्त यूनियनकी मैनेजिंग कमिटीके एक सदस्य ।

कॉ. शङ्करलिंगम :— जी. आई. पी. रेलवे वर्कशॉपके मजदूरोंके नेता । जी. आई. पी. रेलवेमेन्स यूनियनकी मैनेजिंग कमिटीके सदस्य ।

कॉ. जुल्मीराम चौधरी :–जी. आई. पी. रेल्वेमेन्स यूनियनके कोषाध्यक्ष ।

कॉ. जी. एल. पाटिल :– बेस्ट ट्रामके शेड्यूल स्टाफ़ यूनियनके मंत्री ।

कॉ. गांधी :– टेक्सटाईल क्लर्क यूनियनकी मैनेजिंग कमिटीके एक सदस्य ।

कॉ. ठाकुर:– प्रगति प्रिंटिंग प्रेसके सर्वेसर्वा । उनका दोष शायद केवल इतना ही था कि कम्युनिस्ट पार्टीके लिये अपनी प्रेसमें उन्होंने कुछ परचे छापे थे ।

कॉ. दत्तात्रेय सर्वे :– धान मिल्सके एक क्लर्क।

कॉ. बी. एल. गोखले :– बी. बी. एण्ड सी. आई. रेल्वेमेन्स यूनियनकी मैनेजिंग कमिटीके एक सदस्य।

कॉ. के. टी. सुले :– फ़ायरस्टोन रबर वर्क्स यूनियनके सभापति तथा अनेक स्थानीय यूनियनोंके क़ानून-सलाहकार।

कॉ. दोंदे :– मोटर ड्राइवर्स यूनियनके मंत्री।

महाराष्ट्र : कॉ. भैयाजी कुलकर्णी—महाराष्ट्रकी कम्युनिस्ट पार्टीके अध्यक्ष।

कॉ. के. एम. फड़के—महाराष्ट्रकी कम्युनिस्ट पार्टीकी प्रान्तीय कमिटीके सदस्य।

कॉ. पुरन्दरे—जी. आई. पी. रेल्वेमेन्स यूनियन तथा पूनाके कामगारोंके प्रमुख नेता।

कॉ. वसन्त लिमये तथा वी. वी. वैद्य––पूनाकी कम्युनिस्ट पार्टीके सदस्य।

कॉ. नान्देकर तथा नामदेव गायकवाड––महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय कमिटीके सदस्य।

कॉ. कोके तथा शान्ता गोखले — धुलियाके कपड़ा मज़दूरोंकी नेत्री।

कॉ. जी. डी. साने — महाराष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय कमिटीके सदस्य तथा शोलापुरके कपड़ा मज़दूरोंके नेता।

कॉ. मीनाक्षी खाण्डेकर—शोलापुरके कपड़ा मज़दूरोंके नेता।

कॉ. माथुर और गोपाल गोखले—शोलापुरके दस्तकारी करने वाले कपड़ा मज़दूरोंके नेता।

कॉ. मुकुन्द खानोलकर—अम्बरनाथकी कम्युनिस्ट पार्टीके मंत्री।

कॉ. अतूरकर—विम्को माचिस फैक्टरीके मज़दूरोंके नेता।

कॉ. एस. एस. शर्मा तथा आर. जी. गोलिकेरी — बेलगाँवके पार्टी सदस्य।

कॉ. शंकर विठ्ठल सोपे––धुलिया मज़दूरोंके नेता।

कॉ. बुवासाहब नावले—महाराष्ट्र किसान सभाके उपाध्यक्ष।

कॉ. डी. बी. कुलकर्णी—अहमद नगरके किसानोंके सुप्रसिद्ध नेता।

कॉ. पाडुरंग भांगरे—अहमदनगरकी किसान सभाके संगठनकर्ता।

गुजरात : कॉ. दिनकर मेहता–कम्युनिस्ट पार्टीकी गुजरात प्रान्तीय कमिटीके मंत्री।

कॉ. दीनानाथ प्रधान–बी. बी. एण्ड सी. आई. रेलवेमेन्स यूनियनके नेता।

कॉ. गुरुमुख सिंह, कॉ. कार्लेकर, कॉ. महावीर सिंह– बी. बी. सी. आई रेलवेकी दोहद वर्कशॉपके नेता।

कॉ. चन्द्रभाई भट्ट– उपन्यास लेखक तथा मज़दूर नेता।

कॉ. दायाभाई बशी– कैरा जिला किसान सभाके मंत्री।

कॉ. मधुकर मालेकर– सूरत जिलेके ओरपाड़ ताल्लुकके हाली नेता।

मध्यप्रान्तः ३०० से अधिक मज़दूर नेता तथा मज़दूरोंके साथ, निम्न लिखित प्रमुख कम्युनिस्ट नेता गिफ़्तार किये जा चुके है : डॉ. दीवान जी; कॉ. टी. जी. जोशी; कॉ. एस्. एन्. मुले, कॉ. एन. टी. नान्जरेकर तथा जी. सी. एफ़. लेबर यूनियन और पावर हाउसके सभापति कॉ. पी. के ठाकुर।

पूर्वी पंजाबः कॉ० सोहन सिंह जोश एम. एल. ए. प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तथा ५६ दूसरे नेता जिनमें कॉ० जसवन्त तथा का० अर्जुन सिंह प्रमुख हैं।

दिल्लीः स्थानीय प्रमुख नेताओं सहित १७ पार्टी सदस्य।

बिहारः कॉ० सैयद हबीब—प्रान्तीय विद्यार्थी संघके सभापति।

कॉ० ज्ञान विकास मित्र–प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेसके प्रधान मंत्री।

कॉ० चपलेन्दु भट्टाचार्य—जिन्होने अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर संघकी जिनेवा सभामें भारतका प्रतिनिधित्व किया था।

कॉ० विश्वनाथ माथुर–बिहार प्रान्तीय किसान सभाके उप-मंत्री।

कॉ० रामावतार सिंह–सह-सम्पादक ‘ जनशक्ति ’।

आन्ध्रः कॉ० टी० अप्पालस्वामी तथा वी. वेंकटेश्वर शास्त्री—बेज़वाड़ाके सुप्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता।

कॉ० के. एल. नरसिंहराय–एम. एस. एम. रेलवे कर्मचारी यूनियनके प्रधान मंत्री।

त्रावणकोरः कॉ० टी० वी० टामस—त्रावणकोर ट्रेड यूनियन कांग्रेसके अध्यक्ष।

कॉ० आर० संघथन—त्रावणकोर ट्रेड यूनियन कांग्रेसके मंत्री।

कॉ० सी. के. विलायुधन, के. भाष्करन नायर, एम. एन. गोविन्दन नायर तथा ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीके अनेकों नेता।

मैसूर : एन. एल. उपाध्याय—कर्नाटकके प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तथा पार्टी और ट्रेड यूनियनके ३० दूसरे नेता।

कॉ० वसन–कोलारकी सोनेकी खानोंके मजदूरोंके प्रमुख नेता तथा ११ दूसरे नेता।

मलबार : कॉ० के. पी. स्टैनलै--केरल प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कांग्रेसके उपाध्यक्ष, जिनको५० गुण्डोंसे घिरवा कर पिटवाया गया यहाँ तक कि वे बेहोश हो गये।

एक रोज़ गुण्डे कॉ० पी. यशोदाके घरमें घुस गये। वहाँ कुल तीन महिलायें थीं। गुण्डोंने महिलाओंको मारा-पीटा और कॉ० यशोदाको

अधमरा करके सड़कके किनारे खाईमें डाल दिया। वे समझे वह मर गयी हैं।

४ मार्चको केसरगोड़ा तालुकके किसान-संघम पर छापा मारा गया और अखिल भारतीय किसान कान्फ्रेंसकी एक एक पर्ची पुलिस उठा ले गयी।

५ मार्चको प्रान्त भरमें कम्युनिस्ट पार्टी, ट्रेड यूनियन तथा किसान सभाओं के दफ़्तरों पर छापा मारा गया।

६ मार्चको कम्युनिस्ट दैनिक **देशाभिमानी** के दफ़्तर पर छापा मारा गया। १४ मार्चको फिर इस दफ़्तर पर छापा मारा गया जब वहाँ कोई ज़िम्मेदार साथी न था। कॉ. पी. टी. रमनको गिरफ़्तार कर लिया गया।

ख़बर है कि पिछले तीन महीनोंमें मलबारमें ३०० से ऊपर गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं।

मद्रासके दैनिक पत्र **हिन्दू**से ख़बर मिली है कि १२ और १५ तारीख़को उत्तरी मलबारके दो गाँवों—कोरम और तेल्लीगेरी—में किसानों पर गोली चलाकर मलबार स्पेशल पुलिसने ७ कम्युनिस्टोंको जानसे मार डाला और कितनोंको ही घायल कर दिया।

संयुक्त प्रान्त: २७ मार्चको आज़मगढ़ ज़िलेके रौनापुर थानेके किसानों पर गोली चलायी गयी, तीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं और कितने ही किसानोंको बुरी तरह घायल किया गया।

७ एप्रैलको फ़ीरोज़ाबादकी ग्लास फ़ैक्टरियोंके मज़दूरों पर गोली बरसाई गयी।

१३ अप्रैलको कानपुरकी लक्ष्मी रतन काटन मिलके मज़दूरों पर गोली चलाई गयी।

का. रुद्रदत्त भारद्वाजको, जो कम्युनिस्ट पार्टीकी केन्द्रीय कमिटीके सदस्य थे तथा कुछ वर्षों तक पार्टीकी पोलिट ब्यूरो के सदस्य रह चुके थे युक्त प्रान्तकी सरकारने १०४ डिगरी बुखारकी दशा में कैद करके देहरादून जेलमें डाल दिया और उनके प्राण ले लिये।

कॉ. जयदेव कपूर – शहीद भगतसिंहके साथी; का. हाजरा—बेगम अखिल भारतीय महिला सम्मेलनकी प्रमुख कार्यकत्रीको गिरफ्तार करके जेलमें डाल दिया गया है।

इलाहाबादमें: कॉ. रोहिणी कुमार चौबे, कॉ. कामेश्वर प्रसाद अग्रवाल तथा दो अन्य कम्युनिस्ट कार्यकर्ता गिरफ्तार।

Printed by M. B. Rao, at New Age P. Press, 190-B Khetwadi Main Road and Published by him for the Communist Party of India, Raj Bhuvan, Sandhurst Road, Bombay 4.